बंगाल में द्वैध शासन (Dual Government in Bengal)

For U.G.Part-3,Paper-6

क्लाइव ने बंगाल में दूसरी गवर्नरी प्राप्त होते ही बंगाल में **द्वैध शासन** प्रणाली की व्यवस्था लागू की। इस व्यवस्था के अंतर्गत वास्तविक शक्ति तो कंपनी के पास थी परंतु प्रशासन का भार नवाब के कंधों पर था । क्लाइव ने यह प्रशासनिक व्यवस्था बंगाल में **1765 ईसवी** में लागू किया। क्लाइव की इस प्रशासनिक व्यवस्था की मुख्य विशेषता *उत्तरदायित्व रहित अधिकार* तथा *अधिकार रहित उत्तरदायित्व* था ।

12 अगस्त 1765 के फरमान के अनुसार **शाह आलम** ने 26 लाख रुपए वार्षिक के बदले दीवानी का भार कंपनी को सौंप दिया था तथा कंपनी को 53 लाख रुपये निजामत के कार्य के लिए बंगाल के नवाब को देने थे, शेष बचे हुए भाग को अपने पास रखने के लिए स्वतंत्र थी।

दीवान तथा निजाम की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को मिला। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए दो उप- दीवान **बंगाल** के लिए **मोहम्मद रजा खान** तथा **बिहार** के लिए **शिताब राय** को नियुक्त

Scanned with CamScanner

किया। **मोहम्मद रजा खां** को **उप निजाम** के रूप में नियुक्त किया गया। इस प्रकार समस्त दीवानी एवं निजामत का कार्य भारतीयों द्वारा ही चलता रहा। द्वैध शासन व्यवस्था में नियुक्ति से संबंधित तथा नीति निर्माण से संबंधित सारी शक्तियां ब्रिटिश के पास थी जबकि उत्तरदायित्व भारतीयों के पास ।यह व्यवस्था ही दोहरी शासन प्रणाली या द्वैध शासन कहलाई जिसका सीधा तात्पर्य था, दो राजे - कंपनी तथा नवाब। एक के हाथ में शक्ति थी तो दूसरे के हाथ में उत्तरदायित्व।

द्वैध शासन प्रणाली लागू करने के कारण

क्लाइव समझता था कि समस्त शक्ति कंपनी के पास है तथा नवाब के पास सत्ता की केवल छाया मात्र है। उसने प्रवर समिति(Select Committee) को लिखा था कि –' *यह नाम, यह छाया आवश्यक है तथा हमें इसे स्वीकार करना चाहिए।*' इसके पक्ष में उसने निम्नलिखित कारण दिए-

1. यदि कंपनी स्पष्ट रूप से राजनीतिक सत्ता हाथ में ले लेती है तो उसका वास्तविक रूप लोगों के सम्मुख आ जाएगा और संभवत सारे भारतीय इसके विरोध में एकत्रित हो जाएंगे,

Scanned with CamScanner

2. संभवत फ्रांसीसी ,डच तथा डेन जैसी विदेशी कंपनियां सुगमता से कंपनी की सूबेदारी को स्वीकार नहीं करेगी तथा कंपनी को वे कर इत्यादि नहीं देगी जो नवाब के फरमानों के अनुसार उन्हें देने होते थे।
3. स्पष्ट राजनीतिक सत्ता हाथ में लेने से इंग्लैंड तथा विदेशी शक्तियों के बीच कटुता आ जाती और संभवत यह सभी शक्तियां इंग्लैंड के विरुद्ध एक मोर्चा खड़ा कर ले जैसा कि 1778- 80 के बीच अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय हुआ।
4. तत्कालीन समय में इंग्लैंड के पास ऐसे प्रशिक्षित अधिकारी भी नहीं थे जो शासन का भार संभाल लेते। जो थोड़े बहुत लोग कंपनी के पास थे भी वे भारतीय रीति-रिवाजों तथा भाषा से अनभिज्ञ थे।
5. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स उस समय समस्त प्रदेश को ले लेने के पक्ष में नहीं था क्योंकि इससे कंपनी के व्यापार में बाधा पड़ने की संभावना थी। वे लोग प्रदेश के स्थान पर धन में अधिक रूचि रखते थे।

Scanned with CamScanner

6. क्लाइव यह भी समझता था कि यदि वह बंगाल की राजनीतिक सत्ता हाथ में ले लेता है तो संभवत अंग्रेजी संसद कंपनी के कार्य में हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर देगी।

द्वैध शासन प्रणाली से कंपनी को लाभ

1. कंपनी का बंगाल की सत्ता पर पूरा अधिकार हो गया जबकि उनके पास किसी प्रकार के जवाबदेही नहीं थी।
2. अब शासन की विफलताओं के लिए भारतीयों पर दोषारोपण किया जा सकता था जबकि इससे प्राप्त लाभों का उपयोग कंपनी करती थी।

द्वैध शासन प्रणाली के दुष्परिणाम

प्रशासन की जो व्यवस्था क्लाइव ने स्थापित की थी वह अप्रभावी तथा अव्यावहारिक थी। इससे बंगाल में अराजकता तथा भ्रांति फैला । इसके निम्नलिखित दुष्परिणाम सामने आए

1. निजामत की शिथिलता के कारण देश में कानून व्यवस्था की स्थिति कमजोर हो गए। नवाब में कानून लागू करने एवं न्याय देने की सामर्थ नहीं रही थी। कंपनी प्रशासन के

Scanned with CamScanner

उत्तरदायित्व को स्वीकार नहीं करती थी। ऐसी अव्यवस्था में बंगाल वासियों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा।

2. द्वैध शासन से कृषि का हास हुआ। भूमि कर संग्रह करने का अधिकार प्रतिवर्ष अधिकाधिक बोली देने वाले को दिया जाता था जिसका कृषि विकास में स्थाई रूप से कोई रुचि नहीं थी । प्रत्येक वर्ष लगान की राशि बढ़ती चली जाती थी। तंग आकर कृषकों ने खेती करना छोड़ दिया और लगान इतनी कड़ाई से वसूल होता था कि किसानों को अपनी संपदा गिरवी रखकर और बच्चे बेचकर लगान चुकाना पड़ता था। स्वभाविक रूप से ऐसी स्थिति में किसानों की खेती में दिलचस्पी कम हो गई।
3. ऐसे में 1770 ईस्वी में अकाल का पड़ना और कंपनी की तरफ से जनता की सहायता का कोई प्रयत्न नहीं करना अर्थव्यवस्था की दृष्टि से प्रतिकूल साबित हुआ। इस स्थिति में भी कंपनी के कर्मचारियों ने वस्तुओं का मूल्य बढ़ाकर ज्यादा लाभ कमाया।
4. आर्थिक अव्यवस्था की स्थिति तथा कृषि के चौपट होने से व्यापार- वाणिज्य की भी बुरी अवस्था हो गई। कंपनी के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार एवं धन प्राप्ति की लालसा से

Scanned with CamScanner

उनकी व्यक्तिगत आय में तो वृद्धि हुई किंतु बंगाल की दशा कंगाल हो गई ।

5. कंपनी ने भारतीय माल खरीदने के लिए इंग्लैंड से धन भेजना बंद कर दिया फलतः वह बंगाल से प्राप्त राजस्व से ही भारतीय माल खरीदते और उसे विदेशों में बेचते। इस धन को कंपनी की लागत पूंजी समझा जाता था और इसे कंपनी के लाभ में समझा जाता था । इसी प्रक्रिया में 1766- 67 और 68 ईसवी में बंगाल से लगभग 57 लाख पाउंड की निकासी हुई। इस द्वैध शासन का दुष्परिणाम यह हुआ कि बंगाल से **धन निकासी** के फल स्वरुप यह प्रांत दरिद्र हो गया।
6. द्वैध शासन ने उद्योग धंधों को भी नष्ट कर दिया। बंगाल के कपड़ा उद्योग को अत्यधिक हानि हुई। कंपनी ने बंगाल के रेशम उद्योग को निरूत्साहित करने का प्रयत्न किया क्योंकि इससे इंग्लैंड के रेशम उद्योग को क्षति पहुंचती थी।
7. देसी कारीगरों को इतना परेशान किया गया कि वह व्यवसाय छोड़कर , सन्यासी या डाकू बन गए। जुलाहों ने अपने अंगूठे कटवा लिए ताकि उन्हें कंपनी के लिए वस्त्र

Scanned with CamScanner

तैयार ना करना पड़े ।फलतः बंगाल के कुटीर उद्योगों का विनाश हो गया।

8. द्वैध शासन के कारण बंगाली समाज का नैतिक पतन भी आरंभ हो गया। कृषकों ने अनुभव किया कि यदि वह अधिक उत्पादन करता है तो उसे अधिक कर देने पड़ेंगे अतएव केवल गुजारा भर उत्पादन करना सही है। उसी प्रकार जुलाहा जिसे यह आभास हो चला था कि परिश्रम का लाभ वह भोग नहीं सकता इस कारण से वह उत्तम कोटि का उत्पादन करने के प्रति दृढ़ नहीं था। इस प्रकार बंगाल की कार्य संस्कृति भी द्वैध शासन के कारण प्रभावित हुई।

द्वैध शासन के दुष्परिणामों के संदर्भ में **सर जॉर्ज कॉर्नवाल** ने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमंस में कहा था कि- '*मैं निश्चय पूर्वक कह सकता हूं कि 1765- 84 तक ईस्ट इंडिया कंपनी के सरकार से अधिक भ्रष्ट, झूठी तथा बुरी सरकार संसार के किसी भी सभ्य देश में नहीं था।*'

BY :ARUN KUMAR RAI
ASST.PROFESSOR
P.G.DEPT.OF HISTORY
MAHARAJA COLLEGE,ARA.

Scanned with CamScanner